राष्ट्रीय:

Archives

Enter your valid email id and Register yourself to get our daily newsletter

Register

बजट बहुत अच्छा परन्तु घोषणायें कैसे लागू होंगी : जे. डी.अग्रवाल

नई दिल्ली, ९ जुलाई (हिन्दुस्थान समाचार) प्रत्येक परिवार में आजीविका कमाने वाले एक व्यक्ति को न्यूनतम दर पर सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री यदि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक महान वित्त मंत्री बन जायेंगे। यह बात शुक्रवार को यहां भारतीय वित्त संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर जे. डी. अग्रवाल ने इस वर्ष के आम बजट पर एक सार्वजनिक व्याख्यान में कही।

प्रो. अग्रवाल ने आम बजट का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कहा कि विकास, स्थायित्व और समानता इस बजट के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी प्रकार सबको पेय जल और बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है , परन्तु यह लक्ष्य दुसाध्य है। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि इस बजट का प्रभाव क्या होगा और सामान्य आदमी इससे कैसे लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कम्प्यूटर को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है इससे कम्प्यूटर साक्षरता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने गरीबी उन्मूलन के लिए गांवों पर ध्यान दिया, क्षेत्रीय असमानता दूर करने के प्रयास किये और सबको गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य को देने का आश्वासन दिया। ७-८ प्रतिशत तक की सतत वृद्धि दिर बनाये रखने के लक्ष्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने से राज्यों की बहुतसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि कृषि ऋण को अगले तीन वर्षों में दुगना किया जाना, कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करना और सबको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है, परन्तु प्रश्न यह है कि यह सब कैसे होगा?

उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से इस बात की आशंका है कि मुद्रास्फिति बढ़ेगी जिससे जन सामान्य पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा और उसका बजट गड़बड़ा सकता है।

उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य है, परन्तु यह कार्य छह माह में हो सकेगा इसमें संदेह है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बजट में जो दृष्टि अपनाई है, वह लक्ष्य निर्धारित कर उपलब्धि हासिल करने के बजाय खर्च करने की है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इससे फिजूल खर्च बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर भी आशंका जताई कि वित्त मंत्री ने काले धन को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जहां केंद्र के घाटे की चिंता की है, वहीं राज्यों की कोई चिंता नहीं की। इससे वांछित परिणाम प्राप्त होने संदेह है। उन्होंने कहा कि बजट से यह भी नहीं स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी और न ही यह स्पष्ट है कि कितने रोजगारों का सृजन होगा और निवेश की क्या स्थिति होगी। बजट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि घोषणाओं को कैसे लागू किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि गैर कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए थे, खर्च को नियंत्रित किया जाना चाहिए था। इसके लिए वित्त मंत्री आधुनिकतम वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को अपना सकते थे, परन्तु दुर्भाग्य की बात कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बजट के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए थे जिससे रोजगार सृजन होता और देश में समृद्धि आती।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह धारणा भ्रांत है कि कृषि ऋण की वापसी दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सचाई यह है कि किसान ऋण भुगतान के मामले में बहुत सतर्क है जबकि कारपोरेट सेक्टर इस मामले में बहुत ढीला है।

एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि करों की दरें कम से कम होनी चाहिए और कर प्रशासन चुस्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है। ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति कृषि क्रांति के बाद ही आ सकी थी।

संपर्क I About us
©2003, Hindusthan Samachar. All rights reserved to us.